डा. एम.एस. गिल : सर, ऑनरेबल मैम्बर को जो चिन्ता है, वह चिंता हमें भी है, कैबिनेट को भी है और प्रधान मंत्री जी को भी है। बार-बार कहा गया है कि ये जो मामले हैं, जैसे Astro Turf का मामला है, हमने हॉकी एवं दूसरे खेलों के भी कई Turfs लिए हैं, उनके बारे में हम एक-एक चीज़ अखबार में पढ़ते हैं। आगे भी सवाल या चीजें हमारे सामने आएंगी या हमें पता लगेंगी, उन्हें हम अंत तक लेकर जाएंगे।

श्री राजीव शुक्ल : सीवीसी की टेक्निकल कमेटी ने बिल्कुल साफ-साफ बताया है कि ये-ये गड़बड़ियां या अनियमिताएं पाई हैं। अब जो कन्फ्यूज़न है, वह यह है कि किसी की समझ में यह नहीं आ रहा है कि असली जिम्मेदारी किस विभाग की है - अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है, दिल्ली गवर्नमेंट की है या कॉमनवेल्थ ऑर्गनाइजिंग कमेटी की है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से वे यह बताएं कि आखिर इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? यह किसी को मालूम नहीं है, जिसको जो दिख रहा है, वह उसकी की आलोचना कर रहा है। असलियत में किस-किस की क्या-क्या जिम्मेदाररियां हैं, मंत्री जी जरा यह स्पष्ट करें।

डा. एम.एस. गिल : सभापति जी, इसमें बेसिक फोकस कंस्ट्रक्शन के सवालों पर है। जैसा मैंने अर्ज़ किया है, कंस्ट्रक्शन तीन किस्म की हो रही है। हमने कुछ तो स्टेडियम बनाए हैं, मैंने 13 स्टेडियम का जिक्र किया है। सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स - बैडमिंटन एंड स्क्वॉश के लिए एवं यमुना कॉम्प्लेक्स - ऑर्चरी और टेबुल टैनिस के लिए, इन दोनों को डीडीए ने बनाया है। एक-आध छोटा स्टेडियम - त्यागराज स्टेडियम दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया है। बाकी शहर में बहुत कुछ हो रहा है, वह सब दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। जो गेम्स विलेज बनाया गया है, वह एक कंपनी के साथ डीडीए की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है। इसका मैं बहुत सिम्पल जवाब देने की कोशिश करता हूं, जिस-जिस संस्था के सीईओ तक कोई भी इंक्वायरी पहुंचेगी, उस ऑर्गनाइज़ेशन को उस इंक्वायरी का जवाब देना होगा। जो इंक्वायरीज़ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, 'साई' से जुड़ी हुई हैं अथवा सीपीडब्ल्यूडी से जुड़ी हुई हैं - उनका जवाब या तो हम देंगे या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देगी या फिर दिल्ली सरकार अपनी असैम्बली में देगी।

मलिन बस्तियों में बदलते जा रहे शहर

*364. **श्री कप्तान सिंह सोलंकी** : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण अधिकांश शहर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मलिन-बस्तियों में बदलते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस स्थिति की कोई समीक्षा कर रही है अथवा करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सौगत राय): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) और (ख) भारत की जनगणना, 2001 में 50,000 अथवा इससे अधिक की आबादी वाले 640 शहरों तथा कस्बों में स्लम जनसंख्या की गणना की गई है। बाद में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अनुरोध पर, भारत के महापंजीयक ने 20,000 से 50,000 के बीच आबादी वाले 1103 कस्बों की स्लम जनसंख्या की गणना की है। इन 1743 शहरों और कस्बों के डाटा से पता चलता है कि उनमें 524 लाख स्लम जनसंख्या है। वर्ष 2001 में नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन द्वारा सभी शहरी क्षेत्रों की ऐसी जनसंख्या का अनुमान 620 लाख लगाया है। नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन द्वारा मलिन बस्तियों में रह रही आबादी के अनुमान बताते हैं कि भारत में शहरों और कस्बों में मलिन बस्ती आबादी बढ़कर 1981 में 26 मिलियन, 1991 में 46.2 मिलियन और 2001 में 61.8 मिलियन हो गई है जोकि शहरी आबादी का लगभग 21.6% है।

(ग) और (घ) भारत की माननीया राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को जून, 2009 में अपने संबोधन में और प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में "राजीव आवास योजना" (आरएवाई) नामक नई स्कीम के जरिए सरकार के "स्लम मुक्त भारत" के दृष्टिकोण की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद, स्कीम के दिशानिर्देश तैयार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विशेषज्ञों, राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा विकासकत्ताओं के साथ गहन परामर्श किया गया है। इन प्रारूप दिशानिर्देशों का श्री दीपक पारेख की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा व्यापक रूप से मूल्यांकन भी किया गया है। यद्यपि, स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य चल रहा है तथापि मंत्रालय ने स्लम मुक्त शहरी आयोजना स्कीम नामक राजीव आवास योजना का प्रारम्भिक फेज शुरू किया है। इस स्कीम में विशेषज्ञों और समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल करके परिवार-वार स्लम सर्वेक्षण, स्लमों के जीआईएस मानचित्रण, स्लम मुक्त शहरों तथा स्लम मुक्त राज्य योजनाओं के विकास समेत प्रारंभिक कार्यकलाप शामिल हैं। स्कीम के दिशानिर्देश सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिए गए हैं तथा स्लम मुक्त शहरी योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों को 60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

Cities turning into slums

†*364. SHRI KAPTAN SINGH SOLANKI: Will the Minister of HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION be pleased to state:

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

(a) whether it is a fact that most of the cities are turning into slum directly or indirectly due to increasing urbanization;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government is conducting or contemplating any review this regard; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI SAUGATA RAY): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

(a) and (b) The Census of India 2001, conducted enumeration of slum population in 640 cities and towns with population of 50,000 or more. Subsequently, at the request of the Ministry of Housing & urban Poverty Alleviation, the Registrar General of India has conducted enumeration of slum population in 1103 town with population between 20,000 to 50,000. Data for these 1743 cities and towns reveal slum population of 524 lakhs therein. The estimate arrived for all urban areas by the Town & Country Planning Organisation (TCPO) in 2001 is 620 lakhs. Estimates of slum population made by Town and Country Planning Organization (TCPO) reveal that the slum population in cities and town in India increased from 26 million in 1981 to 46.2 million in 1991 and 61.8 million in 2001, amounting to approximately 21.6% of the urban population.

(c) and (d) The President of India, through her Address to both the Houses of Parliament in June 2009 and the Prime Minister, in his Independence Day Address, have announced the Government's vision of a "Slum-free India" through a new scheme "Rajiv Awas Yojana". Subsequent to this announcement, extensive consultations have been held with various Ministries, experts, State Governments, Non-Governmental Organizations, financial and urban experts, private industry etc. to frame the guidelines of the Scheme. These draft guidelines have also been critically appraised by an independent Expert Committee under the Chairmanship of Shri Deepak Parekh. While the finalization of the scheme was underway, the Ministry launched the preparatory phase of

Rajiv Awas Yojana (RAY), called the Slum Free City Planning Scheme. This scheme comprises of the preparatory activities including household wise and slum survey, GIS Mapping of Slums with active involvement of experts and the community for the development of Slum free City and Slum free State Plans. The guidelines of the scheme have been circulated to all States and UTs and a sum of Rs. 60 Crores has been released to States for preparing Slum free City Plans.

श्री कप्तान सिंह सोलंकी : सभापति महोदय, मलिन बस्तियों के कारण शहरों की जो तस्वीर बदल रही है, उसके बारे में इस प्रश्न के द्वारा चिंता व्यक्त की गई थी, लेकिन जो उत्तर आया है, उससे दो चित्र उभरते हैं।

सर्वे के अनुसार जिन शहरों और कस्बों में मलिन बस्तियां हैं, 1981 में जहां वे 26 मिलियन थीं, 1991 में बढ़ कर 46.2 मिलियन हो गईं, यानी उनमें 23 मिलियन या 2 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई, 2001 में 61.8 मिलियन हो गईं, यानी 15 मिलियन या डेढ़ करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई और अब अगर 2011 में आबादी की गणना होगी, तब यह संख्या 72 मिलियन तक हो जाएगी। लगातार यह संख्या इसी तरह बढ़ रही है। हो सकता है कि इसका जवाब हम यह दें कि आबादी बढ़ रही है, इस कारण यह संख्या भी बढ़ रही है और इसको रोकने के लिए देश में कई तरह के प्रयास चल रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री कप्तान सिंह सोलंकी : जो नई सरकार बनी है, यह खुशी की बात है कि उसने 2014 तक "स्लम फ्री इंडिया", यानी मलिन इंडिया की जगह निर्भर इंडिया बनाने का प्रस्ताव किया है। लेकिन यह घोषणा हुए एक वर्ष बीत चुका है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिए।

श्री कप्तान सिंह सोलंकी : अभी तक सरकार ने इसके नाम पर सिर्फ दीपक पारिख की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि 2014 तक स्लम फ्री इंडिया का जो हमने अच्छा चित्र संजोया है, एक वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने उसके बारे में कंक्रीट रूप से क्या किया है?

SHRI SAUGATA RAY: Sir, the hon. Member is correct that the slum population in the country has increased. The Government is very much concerned about the same. That is why, earlier, under the JNNURM, we took up the BSUP, that is, Basic Services for the Urban Poor, and the IHSDP.

Under these programmes, approximately 15 lakh houses have been approval for construction for the poor people. Now, the President of India and the Prime Minister have formulated the Rajiv Awas Yojana. So, it is not correct, what the hon. Member has said, that the Government has been sitting over it. Last year, we have had through discussions with all levels of people, including town planners, State Governments and stakeholders as to how to formulate the Rajiv Awas Yojana. Now, the Ministry has issued guidelines for a slum-free city planning. It is hoped that, soon, the plan would go to the Expenditure Finance Committee, and after it receives approval from the Cabinet, in about three months, we shall be able to announce the concrete guidelines and the concrete steps to be taken under the Rajiv Awas Yojana to make India slum-free. What the hon. Member has said about the Deepak Parekh Committee is also not correct. The Deepak Parekh Committee has submitted its Report, and the Government is deliberating on it. And, it is expected to take a call shortly.

श्री कप्तान सिंह सोलंकी : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जैसा उत्तर आया, मुझे उसी तरह के उत्तर की अपेक्षा थी। दीपक पारिख समिति के नाम पर सिर्फ रिपोर्ट आई है और हमने दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है, जिसे उल्लेखनीय कहा जा सकता हो।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिए।

श्री कप्तान सिंह सोलंकी : सर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ये दिशानिर्देश आपने किसको दिये हैं? ये दिशा निर्देश आपने राज्यों को दिये हैं। तो क्या आप राज्यों के साथ समन्वय करके यह बताएंगे कि मलिन बस्ती के हिसाब से राज्यों की श्रेणी क्या है? यानी, नम्बर 1 राज्य कौन है, नम्बर 2 राज्य कौन है और नम्बर 3 राज्य कौन है, जहां पर मलिन बस्तियां ज्यादा हैं? अगर यह रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो आप शहरों के हिसाब से बता दीजिए और उन शहरों से मलिन बस्ती दूर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ आप क्या कर रहे हैं, कृपया उसका ब्यौरा दे दीजिए।

SHRI SAUGATA RAY: Sir, as I have already informed the hon. Member, the guidelines for a slum-free city have been issued under the Rajiv Awas Yojana. An amount of Rs.60 crores was disbursed to the States to do their planning for a slum-free city, on the basis of whole State-whole city-whole slum approach. Now, this year, the Budget amount of Rs.1,270 crores has been allotted for Rajiv Awas Yojana under this Ministry. So, as soon as the formalities are completed, which is expected within three months, the utilization of the whole money will start. And, I hope that the hon.

Member will be satisfied. The only thing which I want to mention to the hon. Member is that there is no categorization of States according to slums. But there are certain cities which have more slums than others, like, Mumbai has 54 percent slums, which is the highest in the country. Faridabad has 46 percent slums; Aligarh has 45 percent slums. There are more slums in some cities than others. Mumbai has more, while Delhi, Chennai and Bangalore have fewer slums. So, we have categorized the cities as per their slum population.

श्री ब्रजेश पाठक : सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में "मलिन बस्ती मुक्त भारत" की घोषणा की थी और उसकी ताईद माननीय प्रधान मंत्री जी ने हाल ही में की है कि हम "स्लम मुक्त भारत" बनाएंगे। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा सीधा सवाल यह है कि सरकार की जो कथनी है, वह यह है कि वह गरीबों को स्लम से निकाल कर सुन्दर मकान देना चाहती है, लेकिन सरकार की जो करनी है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि जो हिन्दुस्तान में शहरी गरीब लोग हैं, उनकी जनसंख्या कुल शहरी लोगों की 21.6 प्रतिशत है और उनके लिए इन्होंने 60 करोड़ रुपए जारी किये हैं। मेरा पुनः मंत्री महोदय से सवाल है कि क्या 60 करोड़ रुपए में 21.6 प्रतिशत लोगों को आप अच्छा मकान दे पाएंगे? इस बारे में आपका क्या कहना है?

SHRI SAUGATA RAY: I think the hon. Member has missed the important of my statement. I didn't say that Rs.60 crores have been given to make India slum-free. All I have said is that we have formulated guidelines for slum-free city planning sol that, with the help of GIS and other technologies, we can have a plan for making them slum-free. As I had mentioned, in the current year's Budget, already Rs.1270 crores have been allotted to the Ministry of Housing and Poverty Alleviation for starting work on the Rajiv Awas Yojana and, as the Prime Minister has repeatedly said, funds would not be lacking as far as this efforts to make India slum-free is concerned. But, considering the housing shortage in India, it is estimated that six lakh crores of rupees would be necessary to make India totally slum-free or to provide housing to everybody. So, you know, what is a tall order and it would take some time to achieve this purpose.

श्री ईश्वर सिंह सोलंकी : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शहरों और कस्बों में जो बस्तियां हैं, उनमें से लगभग एक-चौथाई बस्तियां, मलिन बस्तियों के अंतर्गत आ गई हैं। देहात का आदमी विशेषकर शहरों की ओर जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन है जिससे देहातों और गांवों के अंदर छोटे-छोटे plots

दिए जाएं, जैसे हरियाणा और पंजाब में दिए गए थे, ऐसे plots देकर उनको वहां आबाद किया जाए ताकि इस आबादी का बढ़ना कम हो?

SHRI SAUGATA RAY: Sir, may I humbly submit that urbanization is an inexorable process. With development, in any country, there would be more and more people migrating to cities because conditions of living in cities are somewhat better than those in rural areas. Already, there is the Indira Awas Yojana of the Government of India in rural areas so that people can build their houses. As far as planning is concerned, the Centre is trying to create counter-magnet cities like, in Delhi, we have in the National Capital Region Planning Board through which we are trying to develop counter-magnet cities so that all the people do not come to Delhi. But the process of migration from rural to urban areas is an economic process and, hence, cannot be stopped.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY: Sir, the State Government of Tamil Nadu has s plan to develop 21 lakh housing units to remove all the huts in slum areas. As of now, Rs.1800 crores have been allotted in this year, especially to construct three lakh houses to replace the huts. Considering the initiative taken by the State Government, I would like to know from the hon. Minister whether, apart from the sixty crores which have been promised by him in the answer, it will be possible for the Ministry to allot more funds to the State of Tamil Nadu?

SHRI SAUGATA RAY: Sir, I may inform, through you, the hon. Member that as far as BSUP in Mission Cities are concerned, in Tamil Nadu, there are already three Mission cities in which 51 projects of slum clearance have been approved and the total cost of these projects is Rs.2327.32 crores. The additional Central assistance is rs.1041.80 crores. I may also mention to the hon. Member that, under the IHSDP for smaller towns, as far as Tamil Nadu is concerned, 84 projects have been approved with a total project cost of Rs.515.88 crores, of which the Central share is Rs.372.10 crores. So, the hon. Member would see for herself that the Centre has allotted considerable amount of money for the work on removal of slums in Tamil Nadu.

*365 [The Questioners (Bharatsinh Prabhatsinh Parmar) was absent]

JNNURM in Gujarat

*365. SHRI BHARATSINH PRABHATSINH PARMAR: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state: